<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>25 जून, 2017</u>

<u>रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधायक, हरियाणा विधानसभा ने निम्नलिखित बयान जारी किया :–</u>

हरियाणा की बजाए – जेवर, उत्तर प्रदेश में नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मंजूरी प्रदेश की जनता के साथ धोखा व अन्याय।

मोदी सरकार + खट्टर सरकार के मायने हैं – हरियाणा से विश्वासघात।

हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त – पिछली केंद्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा चिन्हित की गई थी भूमि।

हरियाणा में होने वाले हजारों करोड़ के निवेश व रोजगार को जबर्दस्त धक्का।

केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश की अनदेखी करके जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मंजूरी प्रदेश की जनता के साथ धोखा, अन्याय व विश्वासघात है, जिसके लिए केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की खट्टर सरकार जिम्मेदार है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस–यूपीए सरकार के समय में वर्ष 2013–14 में हरियाणा के महम के पास इस प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी लगभग मिल गई थी। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार, प्रदेश के हितों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है और हरियाणा में महम, झज्जर या करनाल में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पश्चिम उत्तरप्रदेश के जेवर में मंजूर कर दिया गया है, जो हरियाणा के हकों का सीधा हनन है।

अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मामले में हरियाणा का पक्ष बहुत मजबूत था। हरियाणा में अभी तक एक भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं, जहां से वाणिज्यिक उड़ानें दिन–प्रतिदिन उड़ती हैं। हरियाणा की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लगातार गंभीर प्रयास करते हुए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए महम, झज्जर और करनाल आदि स्थान सुझाए थे, जहां केंद्र सरकार ने अपने विशेषज्ञों का दल भेजकर सर्वे भी करवाया था, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने महम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को स्थापित करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी का फैसला कर लिया था। इसी बीच केंद्र में भाजपा की नई सरकार आ गई और उसने सारी प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तीन साल तक यह परियोजना ठंडे बस्ते में ही रही, लेकिन उत्तरप्रदेश में नई भाजपा सरकार बनने के बाद इसे जेवर को देकर हरियाणा के हितों की बलि चढ़ा दी गई।

हरियाणा के हितों की अनदेखी के बावजूद मुख्यमंत्री, श्री मनोहरलाल खट्टर व हरियाणा के भाजपा सांसदों की इस मामले पर रहस्यमयी चुप्पी से हरियाणा के हितों के प्रति भाजपा नेताओं की उदासीनता का पता चलता है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में भी पंजाब के बराबर हिस्सा होने के बावजूद हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार अभी तक चंडीगढ़ एयरपोर्ट से चंडीगढ़ का सीधा रास्ता भी नहीं दिलवा पाई हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये सभी लोग केवल अपनी कुर्सी

की चिंता कर रहे हैं और उनमें प्रदेश के प्रति हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का आत्मबल नहीं है। हरियाणा के प्रस्ताव के बावजूद भाजपा सरकारों ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम भी शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, चंडीगढ़ रखने से इंकार कर दिया है।

प्रदेश को एयरपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश में अभी तक एक घरेलू एयरपोर्ट भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से नए उद्योग धंधे पनपते, हजारों को रोजगार मिलता, प्रदेश की आय होती। 3000 हेक्टेयर भूमि पर लगने वाले प्रस्तावित एयरपोर्ट में जहां 15000 से 20,000 करोड़ रु. का सीधा निवेश होता, वहीं आसपास के कई जिलों में उद्योग विकसित होते। प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाता, परंतु हरियाणा सरकार के निकम्मेपन के चलते यह बड़ा अवसर हमारे हाथ से निकल गया।

मेरी अपील है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मामले में हरियाणा का पक्ष बहुत मजबूत है और हरियाणा के मुख्यमंत्री को पहल करते हुए केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री के समक्ष इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री कोई मजबूत पहल करते हैं, तो हम सब प्रदेश की जनता के हित में इस बारे में भरपूर सहयोग करेंगे। समय आ गया है कि हरियाणा की खट्टर सरकार हरियाणा प्रदेश के साथ होते हुए विश्वासघात के खिलाफ हरियाणा के हकों की लड़ाई केंद्रीय भाजपा सरकार से लड़े व मनवाए वर्ना हरियाणा की भाजपा सरकार को एक दिन भी अपनी गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं।